वर्ष-14 - अंक 92
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर
शनिवार ,11 जुलाई 2026

RNI.No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाज़ियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

काकोरी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार 3 | 45 डिग्री झुकी इमारत, हर पल गिरने का डर 4 | यूपी में शिक्षकों को अब कैशलेस इलाजः स्वास्थ्य सुरक्षा की नई शुरुआत 02

हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं अयोध्या में विपक्ष पर गरजे CM योगी

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर विपक्ष के हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर जमकर वार कर रहे हैं. सीएम योगी ने आज शुक्रवार को विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था. साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या की भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलकर भरत नगर किया जाएगा जबकि नए नगर निकाय क्षेत्र का नाम मां ज्वाला के नाम पर रखा जाएगा. सीएम योगी अयोध्या में 432 करोड़ रुपये की लागत वाली 217 विकास से जुड़े परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण तथा बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री दिवंगत मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा के अनावरण के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. सीएम योगी ने किसी दल का नाम लिए बगैर कहा, 'आज अयोध्या में जो लोग आस्था की बात कह रहे हैं, इन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था. '

क्या जामा मस्जिद में होगा हनुमान चालीसा: CM योगी

उन्होंने आगे कहा, 'आप सोच सकते हैं कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कोई सरकार ऐसा करवा पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसा करवा पाएंगी? अगर नहीं, तो फिर अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया? ' मुख्यमंत्री ने कहा, 'उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया और हमने अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और सनातन धर्म की राजधानी के रूप में फिर से स्थापित करने का कार्य किया है. ' अयोध्या के कायाकल्प किए जाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि आज अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी और वैभवशाली नगरी के रूप में विकसित हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप अयोध्या अब सौर ऊर्जा आधारित शहर बन चुका है और देश के प्रमुख शहरों में अपनी अलग पहचान बना रहा है.

डबल इंजन की सरकार में राम मंदिर संभवः CM योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'अयोध्या ने आज वह करके दिखाया है जो 500 सालों में नही हो सका था. पीढ़ियों पर पीढियां गई, संतों, राजाओं और समाज के प्रत्येक तबगे ने रामजन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया. लेकिन, जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो देख रहे हैं कि यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं. पिछले दिनों आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है, अयोध्या भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था, यही असली चरित्र है इन लोगों का. 'उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में कई तरह की बाधाएं खड़ी कीं. भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और रामभक्तों पर गोलियां चलवाई. लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ.

भदरसा अब भरत नगर भरत कुंड हुआः CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अयोध्या की भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलने का ऐलान करते हुए कहा, 'इसका नाम अब भदरसा नहीं होगा, बल्कि वो भरत नगर भरत कुंड होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए. ' उन्होंने कहा कि देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है और इसलिए अब भदरसा 'भरत नगर' 'भरत कुंड' के नाम पर जाना जाएगा, वो नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे. पिछले महीने राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर लगातार सवाल उठाए हैं. 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था. विवाद बढ़ने पर 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की थी कि एसआईटी की जांच 'दूध का दूध और पानी का पानी' कर देगी.

राम मंदिर में चढ़ावा गिनने में लगे 20 से ज्यादा कर्मचारियों का इस्तीफा, पेमेंट नहीं होने पर मास रेजीग्नेशन

राम मंदिर चढ़ावा काउंटिंग में लगे बीस से ज्यादा कर्मियों ने एक साथ काम छोड़ दिया है. उनका कहना है कि यहां काम बढ़ा दिया गया है, लेकिन पेमेंट नहीं की गई है. इससे नाराज होकर इन सभी ने इतने बड़े लेवल पर रिजाइन कर दिया. ऐसे में अब दो शिफ्ट की बजाय एक ही शिफ्ट में चढ़ावा काउंटिंग का काम हो सकेगा. पहले सुबह आठ बजे से दो बजे और दो बजे से आठ बजे दो शिफ्ट में चढ़ावे की गिनती होती थी कम स्टाफ के कारण इसे अब एक ही शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका समय 10 बजे से 5 बजे तक तय किया गया है. वहीं सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के बचे हुए कर्मियों को मर्ज कर दिया गया है. ऐसे में अब टीम में 15-16 लोग ही रह जाएंगे. जब तक नये लोग टीम में शामिल नहीं होते तब तक यही व्यवस्था रहेगी. यहां बचे हुए कर्मियों पर वर्क लोड भी बढ़ जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, आज से सेकेंड शिफ्ट में काम कर रहे कर्मियों को सुबह 10 बजे से बुलाया गया है.

आरोपी दान चोरी का पैसा शेयर बाजार में लगाते थे

राम मंदिर चोरी के मामले में एसआईटी जैसे-जैसे अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. एसआईटी के मुताबिक, आरोपी दान के चोरी किए गए पैसों का एक हिस्सा शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए लगाते थे. इसके साथ ही कुछ पैसा वो लोगों को ब्याज पर उधार भी दिया करते थे. इस एंगल से भी पुलिस आरोपियों के जानने वालों के अकाउंट खंगाल रही है.

दान चोरी में एसआईटी का खुलासा

SIT ने पता लगाया है कि दो बड़े अधिकारियों, जिसमें ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा और काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की दान व्यवस्था में बहुत अहम भूमिका थी. इन दोनों ने सुरक्षा के नियमों को ठीक से लागू नहीं किया, जिसकी वजह से मंदिर में आए दान की चोरी और गबन हो गया. स्ट्रक्ष के अनुसार, अनिल मिश्रा ट्रस्ट के पैसे और दान संबंधी सारे कामों के बीच में थे. वे फाइनेंस की देखरेख करते थे, नकदी इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर नजर रखते थे. इसके साथ-साथ बैंक के साथ दान गिनने व जमा करने के नियम (SIT) बनाने में ट्रस्ट की तरफ से काम करते थे. जांचकर्ताओं का कहना है कि इस वजह से अनिल मिश्रा इस बात के लिए सीधे जिम्मेदार थे कि तय किए गए सुरक्षा नियमों को सही तरीके से लागू किया जाए.

कर्मचारियों की नहीं हो रही थी तलाशी

SIT की रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल मिश्रा को अंदरूनी जरिये से पता चला था कि कर्मचारियों की जरूरी तलाशी नहीं ली जा रही थी. फिर भी, उन्होंने नियमों का पालन करवाने या सुरक्षा मजबूत करने के लिए कोई लिखित निर्देश जारी नहीं किए. SIT ने ये भी पाया कि उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जरूरी ड्रेस कोड, गिनती वाले कमरे में निजी सामान ले जाने पर रोक, हुंडी-वाइज गिनती, नोटों की कीमत के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन और रोजाना रिपोर्टिंग को लागू नहीं करवाया.

संक्षिप्त ख़बरें

24 जुलाई के बाद बदलेगा राज्यसभा का गणित, BJP के लिए महिला आरक्षण से परिसीमन तक कई बड़े बिलों का रास्ता साफ

20 जुलाई से से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बीजेपी की राज्यसभा में ताकत बढ़ी हुई होगी. राज्यसभा में बीजेपी की ये ताकत अहम विधेयकों को पारित करने में मदद करेगी. 24 जुलाई के बाद राज्यसभा में बीजेपी का संख्याबल 117 होगा, जो उसके इतिहास की अबतक की सबसे अधिक संख्या है. ऐसे में बीजेपी अपने बूते राज्यसभा में साधारण बहुमत यानी 123 से केवल छह दूर रह जाएगी. इसमें अगर सात मनोनीत और तीन निर्दलीय परिमल नाथवानी, दिलीप रे और कार्तिकेय शर्मा को मिला दें तो बीजेपी साधारण बहुमत के आंकड़े को पार कर 127 पर पहुंच जाती है. सहयोगी दलों के साथ यह संख्या दो तिहाई के आंकड़ेयानी 164 के करीब पहुंच रही है. बीजेपी के सहयोगी दलों में टीडीपी, एआईएडीएमके, जेडीयू और एनसीपी के चार-चार, शिवसेना और यूपीपीएल के दो-दो, आरपीआई-ए, एजीपी, एमएनएफ, एनपीपी, आरएलएम और जनसेना पार्टी के एक-एक सांसद हैं. यानी बीजेपी के सहयोगी दलों की संख्या 26 है. इस तरह एनडीए का आंकड़ 153 तक पहुंच गया है, जो दो तिहाई के आंकड़े से केवल 11 कम है.

बीजेपी की हालिया ताकत में बढ़ोतरी की वजह

बीजेपी की हालिया ताकत में बढ़ोतरी की वजह टीएमसी के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक हैं, जो अब बीजेपी के सदस्य हैं. गुरुवार शाम को ये तीनों बीजेपी में शामिल हुए, जिसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की तीन सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनावों में उन्हें अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया. यह तीनों सीटें इन्हीं के इस्तीफे से खाली हुई थीं, जिस पर इन तीनों की जीत अब महज एक औपचारिकता है.

इन बिलों को पारित कराने की कोशिश में सरकार

अब जिन बिलों को सरकार आगामी मानसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी उसमें महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं. इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान बिल में ही किया जा सकता है. दूसरा विधेयक 30 दिन से अधिक की जेल पर पीएम, सीएम, मंत्री की कुर्सी छीनने वाला संविधान संशोधन विधेयक है, जिस पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट को जल्द सौंपने वाली है. इनके अलावा एफसीआरए बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, एंटी डोपिंग बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के अध्यादेश के बदले विधेयक, कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्यूरिटीज मार्केट कोड जैसे बिल भी सरकार आगामी सत्र में लाने की तैयारी में है.सौरव गांगुली का अंतरराष्ट्रीय करियर कितना शानदार रहा?

सीतापुर में 27 कब्जाधारकों को डीएम कोर्ट का नोटिस, पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता भी शामिल

सीतापुर। शिवपुरी कॉलोनी (पूर्व कंटोनमेंट एरिया) में 25 बीघा भूमि पर बने मकानों, निर्माणाधीन भवनों और प्लाटों के कब्जाधारकों को जिलाधिकारी न्यायालय की ओर से जारी बुधवार को सार्वजनिक नोटिस चस्पा की गई। इसमें सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता समेत 27 लोग शामिल हैं। नोटिस के माध्यम से संबंधित सभी भू-स्वामियों को 24 जुलाई तक जिलाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्वामित्व से संबंधित अभिलेख और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले प्लाईवुड फैक्ट्री की 47 बीघा जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। अभिलेख खंगालने के दौरान यह जमीन भी प्लाईवुड फैक्ट्री की होने की बात सामने आई है। प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से कालोनी के लोगों में

हलचल मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। कार्रवाई को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

छावनी गोरा बारीक में दर्ज है भूमि

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित लगभग 25 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम छावनी गोरा बारीक (पूर्व कंटोनमेंट क्षेत्र) के नाम दर्ज है। इसी भूमि पर वर्तमान में लगभग 27 मकान बने हुए हैं, जबकि कुछ भूखंड अभी खाली या निर्माणाधीन हैं। जिलाधिकारी न्यायालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों को 24 जुलाई तक अपना पक्ष रखने तथा भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

सपा नेता बोले सभी दस्तावेज वैध

सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्त ने प्रशासनिक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास संबंधित भूमि की रजिस्ट्री है। इसके बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भी पूरी हुई। उन्होंने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले सक्षम प्राधिकारी से भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया गया। उनका कहना है कि उनके सभी दस्तावेज पूरी तरह वैध हैं और वह निर्धारित तिथि से पहले ही जिलाधिकारी न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर देंगे।

सिद्धिविनायक दानपेटी लूट की जांच क्यों नहीं? राम मंदिर चंदा चोरी पर एकनाथ शिंदे का विपक्ष से सवाल

महाराष्ट्र विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राम मंदिर चंदा चोरी पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला. शिंदे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता. मामले की जांच की जा रही है. पहले सिद्धिविनायक मंदिर की दानपेटी लूटी गई थी. उस समय इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई गई? मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में शिंदे ने कहा, अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है. धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सच्चाई सामने लाने का प्रयास होना चाहिए. राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता. राम भक्तों को इससे बहुत दुख और वेदना हुई है. इस पर कड़ी जांच और कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

'मोदी-योगी किसी को छोड़ेंगे नहीं'

शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. वे उन्हें (आरोपियों को) सलाखों के पीछे पत्थर तोड़ने के लिए भेजे बिना नहीं रहेंगे. मगर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं, उनके साथियों ने जब सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी लूटने का पाप किया था, तब जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए?

'मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं'

डिप्टी सीएम ने कहा, ?मैं जो बोल रहा हूं, उसके सबूत हैं. मनसे (MNS) के किलेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय यह सब सामने लाया था. यह वास्तविकता है. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. सिद्धिविनायक की दान पेटी पर डाका डालना, क्या यह हमारा हिंदुत्व है? सावरकर को माफीवीर कहने वालों की गोद में बैठना, क्या यह हमारा हिंदुत्व है? बालासाहेब के विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, क्या यह हमारा हिंदुत्व है?

'पाकिस्तानी झंडे लहराना हिंदुत्व है?'

उन्होंने कहा कि साधुओं की हत्या होने पर मुंह बंद करके बैठना, क्या यह हमारा हिंदुत्व है? ?वोटों के लिए आतंकवादियों को प्रचार सभाओं में घुमाना, क्या यह हमारा हिंदुत्व है? चुनाव में पाकिस्तान के झंडे लहराना, क्या यह हमारा हिंदुत्व है?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना पूरे विश्व में फैली हर सनातनी हुआ इससे आहत : अखिलेश यादव

लखनऊ(एजेंसी)। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा व दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाला सनातनी भाजपा और उनके संगी-साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार हैं और इसलिए आहत भी कि उन्होंने भी मंदिर में दान-चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपा के अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार

होना पड़ रहा है।अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दानपात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेगी। भाजपा सरकार ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है।

पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण

चांदीपुर(एजेंसी)। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार, 8 जुलाई 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उपयोगकर्ता (भारतीय सेना) द्वारा तय की गई 60 किलोमीटर की न्यूनतम मारक दूरी के लिए किया गया।रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस सफल परीक्षण ने साबित

किया कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट तय लक्ष्य तक सटीकता के साथ पहुंचने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान रॉकेट को सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे पिनाका लॉन्चर से दागा गया। इससे यह भी साबित हुआ कि एक ही लॉन्चर से अलग-अलग दूरी तक मार करने वाले पिनाका रॉकेटों को दागा जा सकता है।पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एआरडीई) ने विकसित किया है। इसमें हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (एचईएमआरएल) की प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (डीआरडीएल) और रिसर्च सेंटर इमारत (आरसीआई) ने भी तकनीकी सहयोग दिया। वहीं, उड़ान परीक्षण का समन्वय इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट (पीएक्सई) ने किया।

सीतापुर में 12 जुलाई को रोपे जाएंगे 82 लाख पौधे, विकसित होंगे ऊर्जा और कपि वन

12 जुलाई को जिले के विभिन्न हिस्सों में 82 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधरोपण की निगरानी चुनावी मोड में होगी। वन के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भ्रमण करके पौधारोपण का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वन विभाग की साइट पर हर घंटे पौधरोपण का विवरण और फोटो अपलोड होती रहेंगी। इस बार ऊर्जा और कपि दो विशेष वन भी विकसित किए जाएंगे। वन विभाग के साथ ही विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, रेलवे, परिवहन, उद्यान, पंचायत राज आदि विभागों ने अपने कर्मचारियों को पौधों को लगाने और संरक्षित करने का प्रशिक्षण दिलवा दिया है। बड़े स्थलों की बैरीकेडिंग करने के बाद ही पौधारोपण कराने को कहा गया है।झ इस बार वन विभाग के साथ ही अन्य विभागों ने भी रोपे गए पौधों में से कम से कम 75 प्रतिशत को वृक्ष बनाने का संकल्प लिया है। सर्वाधिक 32 लाख 54 हजार पौधे ग्राम्य विकास विभाग की ओर से रोपे जाएंगे। विभाग प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों को आम, इमली, नींबू, कटहल, अमरूद, अशोक, नीम, बकैना आदि के पौधे दिए जाएंगे। दरवाजों पर रोपे जाने के लिए इस बार वन विभाग की ओर सात लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को सहजन के भी पौधे दिए जाएंगे।

वन क्षेत्राधिकारी देंगे रिपोर्ट

इस बार सिर्फ पौधारोपण की नहीं उनकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने सभी वन क्षेत्राधिकारियों को पौधारोपण के बाद सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देने की व्यवस्था भी बना दी है।वन क्षेत्राधिकारियों को अपने विभाग के साथ ही अन्य विभागों की ओर से रोपे गए पौधों की भी मानीटरिंग करनी होगी। ग्रामीणों को

जागरूक करके पौधों की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे।

नैमिषारण्य के आसपास होगा वृहद पौधारोपण

वन विभाग ने नैमिषारण्य के साथ ही आसपास के गांवों में वृहद पौधारोपण की योजना बनाई है। ग्रामीणों से संपर्क करके औषधीय पौधों को लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके अलावा तीर्थनगरी में रिक्त पड़े भूखंडों पर पौधारोपण किया जाएगा।ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई ने यहां रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

पोरबंदर एयरफील्ड के पास 'दृष्टि-10' यूएवी क्रैश, ट्रेनिंग के दौरान हादसा

पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में बुधवार दोपहर भारतीय नौसेना का मानव रहित विमान (यूएवी) दृष्टि-10 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्रोन पोरबंदर एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद नियंत्रण खो बैठा और धारमपुर गांव के पास एक खुले मैदान में क्रैश हो गया। इस हादसे में किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।पोरबंदर के जिला कलेक्टर एस. डी. धनानी ने बताया कि यह यूएवी धारमपुर गांव के पास खुले मैदान में गिरा, जो पोरबंदर शहर से करीब छह किलोमीटर दूर है। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना के अधिकारी और अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि हादसे में किसी व्यक्ति की मौत या चोट नहीं आई है। ड्रोन आबादी से दूर खुले क्षेत्र में गिरा, जिससे

ममता बनर्जी की रैली में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता

बालीगंज(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी की रैली के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हुआ। बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ के बीच निकाले जा रहे इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के ताजा फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे से बुरी तरह उलझ पड़े। इस हंगामे के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है।यह हाई-वोल्टेज ड्रामा उस समय शुरू हुआ जब टीएमसी नेता ममता बनर्जी की अगुवाई में पार्टी का जुलूस बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान वहां भाजपा के समर्थक भी पहुंच गए और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। पहले दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को धक्का देते हुए 'चोर, चोर' के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा था मार्च। यह पूरी झड़प और धक्का-मुक्की कोलकाता के बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ के बीच हुई।

टीएमसी और भाजपा के समर्थक बीच सड़क पर एक-दूसरे से बुरी तरह उलझ पड़े।

संपादकीय

यूपी में शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज: स्वास्थ्य सुरक्षा की नई शुरुआत

उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लागू कर प्रदेश के लाखों शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में पाँच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य केवल चिकित्सा सुविधा देना नहीं, बल्कि शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करना भी है, ताकि वे पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकें। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से किया। क्यों थी इस योजना की जरूरत? शिक्षक समाज का वह वर्ग है जो भविष्य की पीढ़ी तैयार करता है। लेकिन विडंबना यह रही कि कई बार गंभीर बीमारी आने पर शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज के लिए अपनी वर्षों की बचत खर्च करनी पड़ती थी या कर्ज लेना पड़ता था। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करेगी। अब इलाज के समय पहले पैसे की व्यवस्था करने की चिंता कम होगी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा तक पहुंच आसान बनेगी। क्या है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना? इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सरकार के अनुसार यह सुविधा आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इलाज कराया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत नियमित शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया तथा पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। आगे चलकर उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता इस योजना को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप दिया गया है। शिक्षकों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा, संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। यही कार्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज का आधार बनेगा। इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित रहेगी। लाखों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ सरकार के अनुसार इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। विभिन्न जिलों में योजना के शुभारंभ के दौरान प्रतीकात्मक हेल्थ कार्ड वितरित किए गए और हजारों शिक्षाकर्मियों को इस नई व्यवस्था से जोड़ा गया। शिक्षा व्यवस्था पर क्या पड़ेगा प्रभाव? शिक्षक यदि स्वयं स्वस्थ रहेगा तो विद्यालय की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। बीमारी के कारण लंबे अवकाश, आर्थिक तनाव और मानसिक दबाव का असर सीधे शिक्षण कार्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने से शिक्षक अधिक निश्चिंत होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। इसके साथ ही यह योजना सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगी। युवा प्रतिभाओं के लिए सरकारी शिक्षक का पेशा अधिक आकर्षक बन सकता है क्योंकि अब सेवा के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा योजना के शुभारंभ के अवसर पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बीमा सुविधाओं की दिशा में भी पहल की गई। इससे दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की संभावना बढ़ेगी। चुनौतियां भी कम नहीं- किसी भी स्वास्थ्य योजना की सफलता केवल घोषणा से तय नहीं होती। इसके लिए जरूरी है कि— सूचीबद्ध अस्पताल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। कैशलेस इलाज में अनावश्यक देरी न हो। अस्पताल बिना भेदभाव मरीजों को भर्ती करें। भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध रहे। शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी बनाया जाए। यदि इन बिंदुओं पर लगातार निगरानी रखी गई तो योजना का वास्तविक लाभ शिक्षकों तक आसानी से पहुंचेगा। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को समय-समय पर योजना की समीक्षा करनी होगी, अस्पतालों की संख्या बढ़ानी होगी तथा डिजिटल पोर्टल को सुचारु रूप से संचालित रखना होगा। वहीं शिक्षकों को भी समय पर अपना पंजीकरण, ई-केवाईसी और आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखने होंगे ताकि किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। यह केवल इलाज की सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक विश्वास का प्रतीक भी है। यदि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया गया तो यह लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। एक स्वस्थ शिक्षक ही स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला होता है, और यही इस योजना का सबसे बड़ा संदेश है।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

शाहजहांपुर में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से संवर रहा पारंपरिक शिल्पियों का भविष्य

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी अंचलों में सदियों से चली आ रही पारंपरिक कारीगरी को पुनर्जीवित करने और स्थानीय हुनरमंदों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियां अत्यंत दूरगामी और प्रभावी साबित हो रही हैं। जिला स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ उन परिवारों के जीवन में समृद्धि का नया सवेरा लेकर आया है, जो लंबे समय से आधुनिक संसाधनों के अभाव में हाशिए पर थे। शाहजहांपुर जनपद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के सफल संचालन से हजारों शिल्पकारों और श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनके हुनर को एक नया मंच प्रदान किया गया है, जिससे उनका खोया हुआ सामाजिक और आर्थिक सम्मान वापस लौट रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शासन की कल्याणकारी सोच और जिला प्रशासन के कुशल प्रबंधन व जमीनी प्रयासों के परिणामस्वरूप शाहजहांपुर जिले में 1,050 पारंपरिक कारीगरों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। यह संख्या मात्र एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों की आत्मनिर्भरता की जीवंत कहानी है जो पीढ़ियों से बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची और राजमिस्त्री जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं। इन हुनरमंदों को आधुनिकता के इस युग में बाजार की तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि उनका रोजगार न केवल सुरक्षित रहे बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि भी सुनिश्चित हो सके। योजना की संवेदनशीलता और प्रभावशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शाहजहांपुर जनपद में लगभग चार हजार उत्साही और जरूरतमंद युवाओं तथा कारीगरों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे। प्रशासन द्वारा पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसके बाद उन्हें उनकी रुचि और पारिवारिक व्यवसाय के अनुरूप विशिष्ट और निशुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई ताकि वे बिना किसी मानसिक और आर्थिक तनाव के आधुनिक विधाओं को सीख सकें और अपने हुनर को और अधिक निखार सकें। कौशल सुधार की इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सभी चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में चार हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके दैनिक रोजगार में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके और वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने काम को दोबारा शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त, सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के अनुसार आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली टूलकिट पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई गई, जो उनके पुराने और घिसे-पिटे औजारों की जगह नए युग के तकनीकी उपकरणों का समावेश सुनिश्चित करती है।

दर्जी ट्रेड से जुड़े लाभार्थियों को जहां आधुनिक सिलाई मशीनों के साथ-साथ उत्तम श्रेणी की कैंची, सटीक माप फीता और अन्य आवश्यक सहायक उपकरण दिए गए, वहीं नाई, धोबी, हलवाई, राजमिस्त्री, लोहार और बढ़ई जैसे पारंपरिक व्यवसायों के शिल्पियों को भी अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किट प्रदान की गई। पुराने औजारों के कारण जो कार्य पहले अत्यधिक शारीरिक श्रम और घंटों के समय के बाद भी मनमुताबिक फिनिशिंग नहीं दे पाता था, वह अब इन आधुनिक मशीनों की सहायता से बहुत ही कम समय में और वैश्विक स्तर की गुणवत्ता के साथ पूरा होने लगा है, जिससे शाहजहांपुर के इन कारीगरों की कार्यक्षमता और दैनिक आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए डिजिटल पोर्टल को पुन: खोल दिया गया है और इच्छुक कारीगरों से नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार भी प्रशासन ने शाहजहांपुर जनपद के भीतर 1,050 नए लोगों को इस मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सीधे तौर पर लाभान्वित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश एमएसएमई पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, जिससे किसी भी स्तर पर बिचौलियों या मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है और

> **शाहजहांपुर जनपद में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के सफल संचालन से हजारों शिल्पकारों और श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनके हुनर को एक नया मंच प्रदान किया गया है, जिससे उनका खोया हुआ सामाजिक और आर्थिक सम्मान वापस लौट रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शासन की कल्याणकारी सोच और जिला प्रशासन के कुशल प्रबंधन व जमीनी प्रयासों के परिणामस्वरूप शाहजहांपुर जिले में 1,050 पारंपरिक कारीगरों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया।**

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजना का वास्तविक लाभ सीधे पहुंच रहा है। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशी और लचीली प्रकृति है, जिसमें समाज के सबसे पिछड़े और वंचित तबके को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु अठारह वर्ष से अधिक है और जो वास्तव में इन पारंपरिक शिल्पों से आजीविका चला रहा है, वह इस सुनहरे अवसर का हिस्सा बन सकता है। आवेदक की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए ग्राम प्रधान अथवा स्थानीय वार्ड सदस्य की संस्तुति को ही आधार माना गया है, जिससे कागजी औपचारिकताओं के जटिल जाल में फंसे बिना एक आम और अनपढ़ ग्रामीण भी पूरी गरिमा के साथ अपना अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो पा रहा है। जो कारीगर अपने सीमित व्यवसाय को एक बड़े स्तर पर ले जाने या स्वतंत्र लघु उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय बाधाओं को समूल नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के समन्वय से इन हुनरमंदों को दस हजार रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक का अत्यंत रियायती, सुलभ और आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ऋण व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे उद्योगों का जाल बिछ रहा है, जिससे न केवल वे स्वयं आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अपने क्षेत्र के अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार देने की स्थिति में आ रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता के धागे में पिरोने और देश के व्यापक आर्थिक संकल्पों को धरातल पर उतारने में यह योजना शाहजहांपुर जनपद के भीतर एक क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित हुई है। आधुनिक संसाधनों, तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सुदृढ़ता के इस अनूठे संगम ने जिले के लाखों पारंपरिक परिवारों को एक नया संबल, अटूट स्वाभिमान और स्थायी समृद्धि का मार्ग दिखाया है। जमीन पर दिख रहा यह व्यापक बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब सही दिशा में दूरदर्शी नीतियां और पारदर्शी क्रियान्वयन एक साथ मिलते हैं, तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हाथ भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण और सशक्त भूमिका दर्ज कराने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं।

जनपद-शाहजहांपुर

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का व्यावहारिक रास्ता

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप भी हों। स्वच्छ ऊर्जा दरअसल ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। यह ईंधन बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है। फिर भी, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। इन रास्तों को राष्ट्रीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी बिंदु पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत का अपना अनुभव यह बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत लोगों से ही होनी चाहिए। पिछले दशक में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत लगभग 28.6 मिलियन घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ-सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ। ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती हैं: स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए। लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर काम और सहयोगी बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। लेकिन इसकी सफलता इसे समर्थन प्रदान करने वाली प्रणालियों पर निर्भर करती है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सकता है, लेकिन इनकी पूरी क्षमता का लाभ तभी मिल पाएगा जब पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन), भंडारण (स्टोरेज) और ग्रिड प्रबंधन एकसाथ मिलकर काम करें। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारेषण संबंधी बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ-साथ ऊर्जा के भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) और ग्रिड की सुदृढ़ता (ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी) के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर एवं भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है। भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावॉट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) प्रणालियां - जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी-ग्रिड और माइक्रो-ग्रिड - ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थकेयर सेंटरों तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं। भारत की 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक लगभग 4 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकृत एवं भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं। हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है। आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण संबंधी बुनियादी ढांचा, ग्रिड के आधुनिकीकरण, भंडारण प्रणाली और कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों में निवेश बेहद जरूरी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान वित्त पोषण, तकनीक संबंधी साझेदारी और क्षमता विकास के जरिए विकासशील देशों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों के लिए सुदृढ़ एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा प्रणालियां सुनिश्चित करने हेतु मैन्यूफैक्चरिंग, तकनीक, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा। अब जबकि ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता आगे बढ़ रही है, सहयोग की एक ऐसी भविष्योन्मुखी रूपरेखा को मजबूत करने का अवसर है जो सामर्थ्य, बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, विश्वसनीयता, तकनीक की सुलभता, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और सतत विकास का समर्थन करे। चुनौती सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि ऐसे ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की भी है जो सबके लिए सुलभ, किफायती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ दीर्घकालिक आर्थिक विकास और मानव विकास को कायम रखने में सक्षम हों।

(लेखक विद्युत राज्यमंत्री हैं)

भारत के एजेंडा में मानवीयता को पहल

साल 2026 भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साल है। क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम के प्रारंभिक अक्षरों से बने संगठन का अध्यक्ष है। एक जनवरी 2026 को हमने यह अध्यक्षता संभाली है और सितंबर 2026 तक जब हम इस संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, तब तक यह हमारे पास रहेगी। वास्तव में ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में इसके नाम में शामिल इन्हीं पांच देशों के संगठन के रूप में हुई थी। लेकिन बाद के वर्षों में इसका लगातार विस्तार होता रहा और 2024-25 के दौरान मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात तथा इंडोनेशिया जैसे देशों के इस संगठन में शामिल हो जाने से यह अत्यधिक प्रभावशाली संगठन बन गया। भारत इसके पहले साल 2012, साल 2016 और साल 2021 में भी इस संगठन की अध्यक्षता कर चुका है। लेकिन पहले की किसी भी साल के मुकाबले साल 2026 की अध्यक्षता कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब यह बहुत बड़ा संगठन है और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। भारत की मौजूदा अध्यक्षता के समय ब्रिक्स की थीम है, 'बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, को-ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिल्टी' यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। भारत ने अपने इस अध्यक्षता वर्ष के लिए ब्रिक्स का जो नारा चुना है, वह है- 'मानवता पहले। भारत ने अपने चुने गये नारे से ही अपनी प्राथमिकता और दुनिया को लेकर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस बार अपनी अध्यक्षता के दौरान वह इस संगठन के सदस्य देशों पर कुछ प्रमुख चीजों के लिए विशेष जोर दे रहा है, मसलन- डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूती देना, स्वास्थ्य सहयोग को सुदृढ़ आधार देना, जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से ध्यान देना, हरित ऊर्जा पर जोर देना, युवा सहभागिता का आह्वान करना, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना व वैश्विक शासन सुधार पर ध्यान देना। आज ब्रिक्स दुनिया के गिने चुने महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। विश्व की बड़ी आर्थिकी और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह समूह विकसित देशों के प्रभुत्व वाले संस्थानों जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता रहा है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में बड़ी भूमिका दिलाना है।

शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते कर रहे हाई-लेवल मॉनिटरिंग

> **केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जून में 33 प्रतिशत कम बारिश के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और अब यह कमी घटकर 24 प्रतिशत रह गई है। हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से चर्चा में कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में बारिश और रफ्तार पकड़ेगी, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आएगी।**

अल नीनो के संभावित प्रभाव से उपजी मानसून की अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तैयारी, स्पष्ट रणनीति और मजबूत ग्राउंड एक्शन के साथ हालात को संभालने में जुटी है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए सिस्टम पहले से सक्रिय और सतर्क है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जून में 33 प्रतिशत कम बारिश के बाद जुलाई में स्थिति में सुधार आया है और अब यह कमी घटकर 24 प्रतिशत रह गई है। हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से चर्चा में कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में बारिश और रफ्तार पकड़ेगी, जिससे खरीफ बुवाई में तेजी आएगी। शिवराज सिंह ने बताया कि फिलहाल 350.85 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 91.95 लाख हेक्टेयर कम है। मानसून में देरी का असर सोयाबीन और कपास पर पड़ा है, लेकिन किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि और कम पानी वाली फसलों की बुवाई की सलाह दी गई है। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने इस चुनौती के लिए पहले ही अप्रैल से तैयारी शुरू कर दी थी। आईसीएआर के सहयोग से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार कर राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। जून महीने में चलाए गए 'खेत बचाओ अभियान' के तहत 1.24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करीब 1.75 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में बुवाई प्रभावित न हो। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को तेज करते हुए 30 जून तक प्राप्त 1.14 लाख आवेदनों में से 94 हजार से अधिक को स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, ताकि किसी भी संभावित नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिवराज सिंह ने बताया कि अल नीनो की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। अल-नीनो मॉनिटरिंग सेल, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और नियुक्त अधिकारी लगातार मानसून, बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि सरकार केवल हालात पर नजर नहीं रख रही, बल्कि मजबूत प्रक्रियाओं, पर्याप्त संसाधनों और समयबद्ध रणनीति के साथ हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मेष -मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं तथा आर्थिक लाभ की संभावना भी प्रबल रहेगी।

वृषभ -वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिल सकता है और नए प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए हितकारी रहेगा।

मिथुन -मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बड़े भाई या परिवार के सहयोग से पूरा होने की संभावना है।

कर्क -कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई खुशियां लेकर आ सकता है। पहले से अधूरा पड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

सिंह-सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने से लाभ मिल सकता है। पहले से तय कार्य समय पर पूरे होंगे। किसी भी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

कन्या -कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी का व्यवहार आपके मन को प्रसन्न करेगा और पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा। व्यापार में कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा।

तुला -तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही उलझनों का समाधान मिलने से मन हल्का रहेगा। किसी महत्वपूर्ण सूचना के मिलने से भविष्य की योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है।

वृश्चिक-वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। समझदारी और धैर्य के साथ लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के अवसर बन सकते हैं।

धनु -धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से स्नेह और सम्मान प्राप्त होगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगा। यदि किसी यात्रा की योजना है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है। आवश्यक दस्तावेजों का ध्यान अवश्य रखें।

मकर -मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आएगा। व्यापार में विस्तार और आर्थिक प्रगति के लिए समय अनुकूल रहेगा। पहले से बनाई गई योजनाओं को अमल में लाने से लाभ मिल सकता है।

कुंभ -कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे।

मीन -मीन राशि के जातकों का मन आज आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों की ओर अधिक आकर्षित रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को देखने से आपके कई कार्य सहज रूप से पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा और विचारों का आदान-प्रदान होगा।

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

कोटेदारों की मांगों पर मंत्री मनोज पांडेय से वार्ता बेनतीजा

लाभांश बढ़ोतरी पर नहीं बनी सहमति; 28 जुलाई का विधानसभा घेराव बरकरार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिश्रिख़ (सीतापुर) मिश्रिख़ तहसील के वर्मी प्रदेश कार्यलय के जनकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों (कोटेदारों) की प्रमुख मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (एआईएफएसडीए) उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कोटेदारों की सबसे प्रमुख मांग लाभांश (कमीशन) बढ़ोतरी पर कोई सहमति नहीं बन सकी। मंत्री ने अगले पखवाड़े में दोबारा बैठक बुलाकर विस्तृत चर्चा करने का आश्वासन दिया। बैठक में संगठन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कोटेदारों की विभिन्न समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने बकाया भुगतान, अन्नपूर्णा भवन निर्माण एवं

बिजली कनेक्शन, परिवहन ठेकेदारों से जुड़ी समस्याएं तथा अन्य लंबित मुद्दों पर क्रमवार चर्चा की। साथ ही गोवा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में राशन डीलरों को दिए जा रहे लाभांश की प्रमाणित प्रतियां भी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गईं। बैठक के दौरान मंत्री मनोज पांडेय ने प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह से काफी देर तक विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संगठन राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और इसके कार्यों की जानकारी उन्हें पहले से प्राप्त है। मंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना तथा अन्य प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। बैठक के अंत में उन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। हालांकि, संगठन की मुख्य मांग लाभांश (कमीशन) बढ़ाने अथवा न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करने पर कोई ठोस निर्णय या आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद संगठन ने स्पष्ट किया कि पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम यथावत रहेंगे। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 28 जुलाई को लखनऊ के चारबाग स्थित रवींद्रालय से विधानसभा तक पैदल मार्च एवं विधानसभा घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी वार्ता के लिए बुलाएगी, संगठन बातचीत के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब तक कोटेदारों की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेशभर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का अभियान जारी है। यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण के बहिष्कार पर भी विचार करेगा। बैठक में जिला महासचिव सीतापुर विशाल रस्तोगी, आलोक मिश्रा गोंदलामऊ,सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे

काकोरी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र में ऑटो खरीदने निकले युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा गया मोबाइल फोन, ?4,800 नकद तथा घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, दिलीप रावत (30 वर्ष) 7 जुलाई को नया ऑटो खरीदने के लिए अपने घर से ?80 हजार लेकर गांव के ही मुजीब उर्फ मुन्ना के साथ निकला था।

इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर काकोरी थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की। इसी दौरान दिलीप का शव आगरा एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड के किनारे बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुजीब उर्फ मुन्ना (30 वर्ष) निवासी नकटौरा, दोना थाना काकोरी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ऑटो खरीदने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों ने साथ में शराब पी। इसके बाद मोबाइल और पैसों के लालच में उसने गमछे से दिलीप का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक्सप्रेस-वे किनारे फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गया।भौगोलिक संदर्भ पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का मोबाइल, ?4,800 नकद तथा घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (क्क32ञ्ञ-4614) बरामद किया है। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।

दधीचि कुंड तीर्थ में हजारों मछलियों की मौत, ऑक्सीजन की कमी बनी मौत की वजह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिश्रिख (सीतापुर)। विश्व प्रसिद्ध दधीचि कुंड तीर्थ में गुरुवार को हजारों मछलियां मृत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुंड में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखाई देने पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने चिंता जताई। कर्मचारियों द्वारा कुंड से मृत मछलियों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं तीर्थ के प्रधान पुजारी राहुल शर्मा ने बताया कि यह समस्या पहली बार नहीं हुई है। उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में कुंड में ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो जाती है। यदि प्रशासन समय रहते आवश्यक इंतजाम कर दे तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक श्रद्धालु द्वारा कुंड में दो ऑक्सीजन मशीनें लगवाई गई थीं, जो पानी को फिल्टर कर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने का कार्य करती थीं। लेकिन लगभग तीन माह पूर्व दोनों मशीनें खराब हो गई और मरम्मत के लिए नगर पालिका मिश्रिख भेजी गई। आरोप है कि अब तक उनकी मरम्मत कर दोबारा स्थापित नहीं कराया गया है। इसके अलावा कुंड में पानी को शुद्ध रखने और मछलियों के संरक्षण के लिए दवा युक्त चार विशेष टंकियां भी लगाई

गई थीं, जिनसे धीरे-धीरे दवा का रिसाव होकर पानी की गुणवत्ता बनाए रखी जाती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे टंकियां भी लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हैं, जिससे समस्या और बढ़ गई है।घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका की ओर से कुंड में चूने का छिड़काव कराया गया तथा पानी की व्यवस्था शुरू कराई गई। साथ ही कर्मचारियों द्वारा मृत मछलियों को निकालने का कार्य जारी है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दधीचि कुंड की नियमित निगरानी कर ऑक्सीजन मशीनों को शीघ्र चालू कराया जाए तथा जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि छोटे खुदरा दुकानदारों और फेरी वालों का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बिराहिमपुर में सीसीटीवी घोटाले का बड़ा खुलासा! विरोधियों के घरों पर कैमरे, सचिव की वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

.....बिराहिमपुर में त्रिनेत्र योजना पर बड़ा घोटाला! प्रधान पर सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद (लखनऊ)। ग्राम पंचायत बिराहिमपुर में पंचायत की सुरक्षा के लिए लगाई गई त्रिनेत्र (CCTV) योजना अब गंभीर विवादों में घिर गई है। ग्राम प्रधान रामशंकर कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी योजना का दुरुपयोग करते हुए चुनावी रंजिश के चलते अपने विरोधियों के घरों की ओर CCTV कैमरे लगवाए, जिससे ग्रामीणों की निजता और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कैमरों का उद्देश्य पूरे गांव की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि कुछ विशेष परिवारों और विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना था। इससे महिलाओं और परिवारों की निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कैमरों की निगरानी के लिए लगाई गई स्ष्ठ टीवी ग्राम प्रधान रामशंकर कश्यप ने अपने घर पर लगवा ली, ताकि वह दिन-रात कैमरों की रिकॉर्डिंग और लाइव फुटेज देख सकें।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की संपत्ति किसी निजी आवास में रखना सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पंचायत सचिव का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल रिकॉर्डिंग में पंचायत सचिव कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने केवल आठ कैमरे लगाने की बात कही थी, लेकिन प्रधान ने अपनी मर्जी से अधिक कैमरे लगवा दिए। साथ ही सचिव का यह भी कथित आरोप है कि भुगतान कराने के लिए उन पर लगातार चेक पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है और अवैध तरीके से सरकारी धन निकालने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की दबंग छवि के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या त्रिनेत्र योजना में कथित भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग और ग्रामीणों की निजता से जुड़े इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? या फिर यह मामला भी शिकायतों तक ही सीमित रह जाएगा?

मऊ में 5.30 करोड़ की लागत से बनेगा 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया शिलान्यास

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ/मऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को मऊ जनपद के बंधा रोड स्थित प्रस्तावित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्युत अवसंरचना को आधुनिक और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि लगभग 5.30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस उपकेंद्र की क्षमता 5+5 एमवीए होगी। इसके तहत चार नए 11 केवी फीडरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मौजूदा विद्युत उपकेंद्रों पर भार कम होगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक संतुलित एवं प्रभावी बनेगी।

उन्होंने कहा कि नए उपकेंद्र के शुरू होने से पटन टोला, व्यारी टोला, संस्कृत पाठशाला, हरिकेशपुरा, सदर चौक, मलिक टोला, हट्टी मदारी, औरंगाबाद, हनुमान घाट, ऑफिसर्स कॉलोनी, रेलवे क्वार्टर, गायघाट, खालसा और ख्वाजाजहांपुर सहित कई क्षेत्रों के लगभग 4,000 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इन इलाकों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ए.के. शर्मा ने कहा कि उपकेंद्र के संचालन से 11 केवी लाइनों की लंबाई कम होगी, जिससे तकनीकी हानियां और फॉल्ट की घटनाएं घटेंगी। साथ ही ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली बाधित होने जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तथा विद्युत वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए नए विद्युत उपकेंद्रों, लाइनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन से हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

होमगार्ड्स मुख्यालय में धर्मवीर प्रजापति ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने गुरुवार को होमगार्ड्स मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभागीय कार्यों की प्रगति, सेवा गुणवत्ता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में 12 जुलाई को आयोजित होने वाले बृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों पर विशेष चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर संचालित होमगार्ड कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों तथा उनके आश्रित परिवारों को योजना से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना होमगार्ड परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों के कल्याण और सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

रायबरेली में सर्विस रोड निर्माण के लिए 1.30 करोड़ रुपये जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली जनपद में प्रतापगढ़ शाखा की बायीं पटरी स्थित सर्विस रोड के निर्माण कार्य के लिए 1.30 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी कर दी है। इस संबंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। जारी धनराशि से प्रतापगढ़ शाखा की बायीं पटरी पर किमी 0.100 से 5.100 तक ब्रिक ऑन एज सोलिंग का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।

इससे परियोजना के कार्यों में तेजी आएगी और क्षेत्र के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। शासनादेश में संबंधित मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाए। साथ ही परियोजना के प्रत्येक चरण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राजधानी में वर्षभर होंगे एक दर्जन से अधिक सांस्कृतिक आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राजधानी लखनऊ में महापुरुषों की जयंती, राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक घटनाओं और आस्था स्थलों से जुड़े अवसरों पर एक दर्जन से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इन आयोजनों में देश-प्रदेश के ख्यातिप्राप्त कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार को बताया कि इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक घटनाओं और राष्ट्रीय महत्व के अवसरों से नई पीढ़ी को परिचित कराना है। साथ ही स्थानीय कलाकारों को सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़कर उन्हें मानदेय के माध्यम से आर्थिक संबल भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्ययोजना के तहत 9 अगस्त 2026 को बाजनगर शहीद स्मारक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 19 दिसंबर 2026 को काकोरी बलिदान दिवस तथा अक्टूबर में गिरजा देवी समारोह के अवसर पर भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। दिसंबर 2026 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी स्मृति में विशेष सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 24-25 जुलाई 2026 को 'रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एवं आर्कियोलॉजिकल कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पुरातत्व निदेशालय के सहयोग से होगा। इसी क्रम में 11 नवंबर 2026 को बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय उत्सव आयोजित किया जाएगा। वहीं नवंबर-दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की कठपुतली परंपरा पर आधारित 'पुतुल पर्व' का आयोजन भी प्रस्तावित है। जनवरी 2027 में यूपी दिवस के अवसर पर राज्य ललित कला अकादमी के सहयोग से पांच दिवसीय सैंड आर्ट शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 जनवरी 2027 से राज्य संग्रहालय, लखनऊ के तत्वावधान में संग्रहालय विज्ञान एवं प्राचीन सिक्कों पर आधारित छह दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त 19 अगस्त 2026 को मोक्ष सप्तमी पर एक दिवसीय संगोष्ठी तथा 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को कत्थक सम्राट गुरु लच्छू महाराज समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में देश-प्रदेश के नामचीन कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सौजन्य से संपन्न होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को व्यापक पहचान मिलेगी और स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा।

पदोन्नति पर खंड शिक्षा अधिकारी को फूल-मालाओं से लाद कर विदा किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी रेउसा राम जनक वर्मा की पदोन्नति के पश्चात् आज उन्हें कार्यमुक्त किया गया।हाल ही में उनकी पदोन्नति बाराबंकी जनपद में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर होने से रेउसा विकास खण्ड के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं में हर्ष व्याप्त है। ब्लाक के सभी शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी रहे रामजनक वर्मा को बधाई दी है। एक सादे समारोह में वृहस्पतिवार को उन्हें फूल-मालाओं से लाद कर विदा किया गया। कार्यक्रम का संचालन संदीप मिश्र ने किया। राम जनक वर्मा ने कहा कि सभी शिक्षकों का निरंतर सहयोग मिला। सभी से मिला स्नेह और सहयोग हमेशा याद रहेगा। सेवाकाल में कभी भी हमें अड़चन नहीं आई। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पाण्डेय एवं मंत्री सच्चिदानंद अवस्थी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव एवं मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सह मंत्री मनीष शाक्य, शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं मंत्री कुलदीप श्रीवास्तव, समस्त एआरपी, शिक्षकगण एवं बीआरसी स्टाफ के लोगों ने राम जनक वर्मा को विशाल माला पहनाकर, पुष्पगुच्छ एवं स्मृतिचिन्ह देकर विदाई दी।इस अवसर पर समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान का असर, दुर्घटनाओं और जनहानि में आई उल्लेखनीय कमी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान और सख्त प्रवर्तन का सकारात्मक असर अब आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। परिवहन विभाग द्वारा मार्च से मई 2026 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि और हिट एंड रन मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि प्रभावी कानून प्रवर्तन, आधुनिक निगरानी व्यवस्था और जनजागरूकता के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने ओवरस्पीडिंग, यातायात नियमों के उल्लंघन और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत व्यापक कार्रवाई की। मोटर वाहन अधिनियम की धारा-19 के तहत तीन माह में 1,246 चालकों को नोटिस जारी किए गए। इस दौरान 797 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि गंभीर मामलों में 20 ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए गए।

नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा पर महापौर सख्त, अवैध कब्जों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ नगर निगम के संपत्ति विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम की भूमि एवं संपत्तियों के अभिलेखीकरण, संरक्षण, अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई तथा कब्जामुक्त कराई गई भूमि की वर्तमान स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव जी, प्रभारी अधिकारी संपत्ति रामेश्वर प्रसाद जी समेत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल तथा संपत्ति विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सुषमा खर्कवाल ने निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र में ऊसर, बंजर, नवीन परती, चारागाह, तालाब तथा अन्य शेष मदों में दर्ज भूमि का ग्रामवार विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के पास प्रत्येक गांव और प्रत्येक श्रेणी की भूमि का स्पष्ट एवं अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। महापौर ने अब तक अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्थल की मौके पर वर्तमान स्थिति की जांच की जाए और स्पष्ट किया जाए कि कब्जामुक्त कराई गई भूमि अभी खाली एवं सुरक्षित है अथवा उस पर दोबारा अवैध कब्जा हो गया है। महापौर ने नगर निगम की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अब तक किए गए कार्यों की अलग-अलग जानकारी मांगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन संपत्तियों पर बाउंड्रीवॉल बनाई गई है, तारबाड़ कराई गई है अथवा सूचना पट लगाए गए हैं, उनका पूरा विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शेष असुरक्षित संपत्तियों की पहचान कर उनके संरक्षण की कार्ययोजना बनाई जाए। बैठक में महापौर ने विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की संपत्तियों पर अवैध कब्जे से संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि पार्षदगणों और क्षेत्रीय नागरिकों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनके क्षेत्रों में नगर निगम की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसी शिकायतों की प्रतियां कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती हैं, इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। महापौर ने संपत्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के पास तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, कानूनगो और लेखपाल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद नगर निगम की संपत्तियों को कब्जामुक्त कराकर बाउंड्रीवॉल, तारबाड़ और सूचना पट के माध्यम से सुरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर सुषमा खर्कवाल एवं नगर आयुक्तगौरव कुमार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपालों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन फील्ड में निकलें और अपने-अपने क्षेत्रों में नगर निगम की जमीनों की नियमित निगरानी करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी केवल कार्यालयी अभिलेखों तक सीमित न रहें, बल्कि मौके पर जाकर भूमि की वास्तविक स्थिति देखें, अवैध कब्जे की पहचान करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक बार कब्जामुक्त कराई गई भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा न हो, इसके लिए नियमित स्थलीय निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जाए। संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संपत्तियों की लगातार निगरानी करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाए।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निर्माण कार्यों और जलभराव से निपटने की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने गुरुवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों एवं वर्षा ऋतु के दृष्टिगत जलभराव से निपटने की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैसरबाग स्थित चकबस्त परिसर, विभिन्न पंपिंग स्टेशनों एवं कश्मीरी मोहल्ला स्कूल में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सबसे पहले कैसरबाग स्थित चकबस्त परिसर का निरीक्षण किया। यहां नगर निगम जोन-1 का जोनल कार्यालय तथा भूमिगत दो मंजिला मल्टीलेवल पार्किंग प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण न होने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इसे 31 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। साथ ही अधिकारियों को कार्य की नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान चीफ इंजीनियर सिविल महेश वर्मा एवं अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा उपस्थित रहे। इसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने वर्षा ऋतु के दृष्टिगत जलभराव से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जोन-1 स्थित घसियारी मंडी, वजीरगंज, जोन-6 स्थित सरकटा नाला तथा जोन-3 स्थित हार्डिंग-2 पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी स्थानों पर पंपिंग स्टेशन क्रियाशील पाए गए। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा के दौरान पंपिंग स्टेशनों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध मजबूत करने पर मोदी का जोर

नई दिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का बृहस्पतिवार को आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने और प्रस्तावित सीईसीए को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की। मोदी ने मेलबर्न में 'ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सीईओ फोरम' और 'इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इन कार्यक्रमों को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ संयुक्त रूप से संबोधित किया।भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन कार्यक्रमों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। सीईओ फोरम को संबोधित करने के बाद मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, '' 2023 से इस फोरम ने उल्लेखनीय गति हासिल की है, जो हमारी आर्थिक साझेदारी में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। इस संवाद में शामिल होने और हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अपने दृष्टिकोण को साझा करने

मोदी ने मेलबर्न में 'ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सीईओ फोरम' और 'इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इन कार्यक्रमों को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ संयुक्त रूप से संबोधित किया।भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन कार्यक्रमों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। सीईओ फोरम को संबोधित करने के बाद मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, '' 2023 से इस फोरम ने उल्लेखनीय गति हासिल की है, जो हमारी आर्थिक साझेदारी में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

के लिए मैं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आभार व्यक्त करता हूं। मोदी ने कहा कि उन्होंने विमानन, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाएं, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, '' भारत विकास एवं नवाचार के लिए बेजोड़ अवसर प्रदान करता है। मैंने कारोबारियों को भारत में निवेश करने और नवाचार करने के लिए आमंत्रित किया।'' एमईए के बयान के अनुसार, सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत की ''मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल बदलाव और बढ़ रहा नवाचार परिवेश ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए कारोबारी अवसर पैदा कर रहे हैं।''उन्होंने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर पूरकता का भी उल्लेख किया और विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, बुनियादी ढांचा, कृत्रिम मेधा, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल आर्थिक गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध ''व्यापक अवसरों'' को रेखांकित किया। मोदी ने कहा कि भारत का विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता ''दोनों पक्षों के लिए लाभकारी प्रस्ताव'' है और ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। एमईए ने कहा, '' उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल विकास में गहरा सहयोग दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के साथ-साथ उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा।

45 डिग्री झुकी इमारत, हर पल गिरने का डर, हाथों से मलबा हटाकर जिंदगियां बचा रही एनडीआरएफ

पुणे(एजेंसी)।महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड़ के मोशी इलाके में गुरुवार को भी राहत और बचाव का काम चलता रहा। यहां स्थित एक कचरा प्रबंधन संयंत्र की तीन मंजिला इमारत बुधवार को ढह गई थी। मलबे के नीचे से अब तक एक शव को बाहर निकाला गया है। बचाव दल ने नौ लोगों को जिंदा सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। यह इमारत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर बनी हुई थी जिस पर पुराने कचरे का पहाड़ जैसा ढेर गिर गया था। कचरे के इस दबाव के कारण पूरी इमारत जमींदोज हो गई और वहां काम कर रहे करीब 18 लोग मलबे में दब गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। शुरुआती कुछ ही घंटों में सात लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया था। इसके बाद देर रात दो और लोगों को सुरक्षित निकाला गया जिससे बचाए गए लोगों की संख्या नौ हो गई। मौके पर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार काम कर रही हैं।बचाव अभियान को लेकर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कमांडेंट एसबी सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह एक शव बरामद हुआ है और दो अन्य

शवों का पता चल गया है। एसबी सिंह ने कहा, 'एनडीआरएफ अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हमने हाथों से खुदाई कर एक संकरी जगह बनाई है और उसी रास्ते से अंदर पहुंच रहे हैं। अब तक तीन शवों का पता चल चुका है जिनमें से एक को बाहर निकाल लिया गया है।' उन्होंने बताया कि दूसरा शव मलबे में दूर से दिखाई दे रहा है लेकिन उसे बाहर निकालने में काफी समय लग सकता है।इमारत का ढांचा पूरी तरह अस्थिर होने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारियों के अनुसार इमारत लगभग 45 डिग्री तक झुक गई है जिससे उसके दोबारा गिरने का डर बना हुआ है। एसबी सिंह ने कहा, 'हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इमारत दोबारा न गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो बचावकर्मी भी मलबे में फंस सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर फंसे लोगों पर और मलबा न गिरे।' बचाव कार्य में भारी मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मशीनों से होने वाले कंपन के कारण इमारत का बाकी हिस्सा भी गिर सकता है। बचावकर्मी हाथों से ही धीरे धीरे मलबे को हटा रहे हैं ताकि फंसे हुए लोगों और खुद उनकी जान को कोई खतरा न हो।

बच्चों को ब्रोंकियल अस्थमा से कैसे बचाएं

बच्चों में बढ़ती सांस संबंधी समस्याओं के बीच योग को स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से पीएम ई-विद्या पर एक विशेष कार्यक्रम 'योगशक्ति-बच्चों में ब्रोंकियल अस्थमा का योगिक प्रबंध' आयोजित किया गया है। इस लाइव सत्र में योग विशेषज्ञों ने बच्चों में ब्रोंकियल अस्थमा के प्रबंधन में योग की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की तथा उपयोगी योगाभ्यासों का प्रदर्शन भी किया गया। एनसीईआरटी के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन 7 जुलाई 2026 की सुबह पीएम ई-विद्या चैनल 6 से 12 पर किया गया। यह सत्र विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक सभी लोगों के लिए उपयोगी रहा। इस कार्यक्रम में योग विशेषज्ञ कृष्ण कुमार गुप्ता, योग प्रशिक्षक एवं एमडीएनआईवाई के पूर्व छात्रों ने स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त योग पद्धतियों और उनके लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों के साथ बच्चों को संवाद का अवसर भी मिला। गौरतलब है कि योग को समग्र स्वास्थ्य और जीवनशैली का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। विभिन्न अध्ययनों में यह संकेत मिला है कि चिकित्सकीय उपचार के साथ पूरक रूप में अपनाए जाने पर योग बच्चों में अस्थमा से जुड़े कुछ

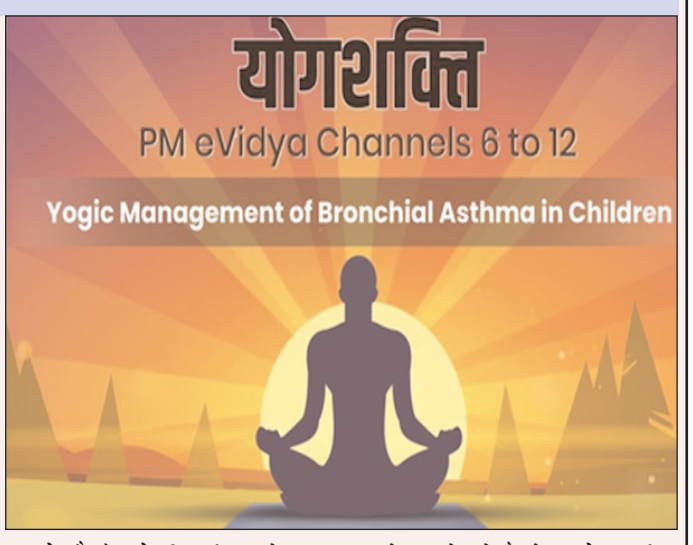

लक्षणों और फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार लाने में सहायक हो सकता है। यह पहल विद्यार्थियों और अभिभावकों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम से जुड़कर प्रतिभागी यह जान सके कि नियमित योगाभ्यास किस प्रकार बच्चों के समग्र स्वास्थ्य, श्वसन क्षमता और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। अभी 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनियाभर में मनाया गया था। इस अवसर पर देशभर में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम के अनुरूप लोगों ने स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाने का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में छात्रों के सामूहिक योग सत्र आयोजित हुए।

योग प्रशिक्षकों ने प्राणायाम, आसन और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों के मुताबिक कि नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है।

साइटिका के दर्द में राहतकारी समय पर जांचचार

साइटिका कोई गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि साइटिक नर्व पर दबाव या जलन होने के कारण अलग तरह का कमर दर्द होने की स्थिति है। साइटिका व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। लेकिन सही समय पर जांच और उपचार से अधिकांश मरीजों में सुधार संभव है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर अधिकांश लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। असल में हमारी रीढ़ की हड्डी कई छोटी-छोटी कशेरूकाओं या मनकों से बनी होती है। कमर के हिस्से में एल-4, एल-5, एस-1, एस-2, एस-3 जैसे मनके होते हैं। इन मनकों के बीच एक नरम डिस्क और बहुत पतली नसें होती हैं, जो झटकों से बचाने का काम करती है। साथ ही इनके बीच से बहुत पतली नसें निकलती हैं, जो आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं और साइटिक नर्व बनाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नस साइटिका कमर से निकलकर कूल्हों, जांघों, पिंडलियों और पैरों तक जाती है। कई कारणों से साइटिका नस के दबने पर उसमें सूजन-जलन के साथ असहनीय दर्द होने लगता है।आयुर्वेद में साइटिका को गृध्रसी रोग कहा जाता है और इसे वातजन्य रोगों की श्रेणी में रखा गया है। जिन लोगों के शरीर में वात यानी वायु अधिक बनती है या जिनकी नसें और मांसपेशियां कमजोर होती हैं,उन्हें साइटिका और कमर दर्द की समस्या ज्यादा होती है। यह समस्या मुख्य रूप से बढ़े हुए वात दोष और दूषित कफ दोष के कारण उत्पन्न होती है। शरीर में वात दोष बढ़ने के कारण रीढ़ की नसें कमजोर होने लगती हैं, उनमें ऐंठन या दवाब बढ़ जाता है और गृध्रसी रोग उत्पन्न होता है। शरीर में बढ़ा हुआ वात डिस्क के अंदर मौजूद छल्लों के बीच के फ्लूड को सुखा देता है। यह फ्लूड लगभग 80

प्रतिशत पानी और 20 प्रतिशत प्रोटीन व कैल्शियम से बना होता है। फ्लूड सूखने के कारण छल्ले आपस में टकराने लगते हैं। उनके बीच की जगह खत्म हो जाती है और किसी न किसी नस पर दबाव पड़ने लगता है। जब नस दबती है, तो पूरी टांग में दर्द शुरू हो जाता है।साइटिका दर्द कमर से शुरू होकर एक पैर तक जाता है। पैरों में कमजोरी, झनझनाहट या सुन्नपन भी महसूस होती है। बैठने पर टांगों में सुन्नपन आने लगता है। लेटने पर दर्द ज्यादा महसूस होता है। जब व्यक्ति चलता है, तो शरीर गर्म होने लगता है और धीरे-धीरे साइटिका का दर्द कम होने लगता है। पैर में कमजोरी महसूस होना।जब दोनों पैरों में कमजोरी आने लगे। पेशाब आदि पर नियंत्रण कम हो जाए। दर्द लगातार बढ़ता जाए। पैर सुन्न होने लगें। चलने में कठिनाई हो। चोट लगने के बाद कमर से पैर तक तेज दर्द शुरू हो तो डाक्टरी परामर्श लेना चाहिये। डॉक्टर सबसे पहले शारीरिक परीक्षण करते हैं। नस या डिस्क की स्थिति देखने के लिए एक्स-रे, एमआरआई, नर्व कंडक्शन टेस्ट किए जाते हैं। साइटिका के होने वाले दर्द की प्रमुख वजहें ये हैं : रीढ़ की हड्डी में उम्र के साथ होने वाले बदलाव, वजन ज्यादा होना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना या फिर शारीरिक गतिविधियां या व्यायाम बिल्कुल न करना, बहुत देर तक खड़ा रहना या लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, भारी वजन उठाने, गिरने या कमर में चोट की वजह से डिस्क का खिसकना या डिस्क का अपनी सीध से बाहर निकल जाना, डिस्क दबने से मनकों के बीच का गैप कम हो जाना या ज्यादा बढ़ जाना, वात बढ़ाने वाले आहार (जैसे-बीन्स, अंकुरित अनाज, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, सूखा और ठंडा भोजन,या फिर कड़वे और कसैले रस वाले पदार्थ) का सेवन अधिक करना। मरीज की स्थिति के हिसाब से दर्द और सूजन कम करने वाली दवाइयां दी जाती हैं। गंभीर मामलों में इंजेक्शन या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। मरीज को फिजियोथेरेपी,स्ट्रेचिंग, रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों की मजबूती के लिए एक्सरसाइज कराई जाती हैं। उसे लंबे समय तक एक जगह बैठ कर काम न करने, उठने-बैठने, चलने-फिरने में सही पॉश्चर अपनाने, भारी वजन न उठाने, वजन नियंत्रित करने के लिए एक्टिव रहने और क्षमतानुसार दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से साइटिका दर्द के निवारण हेतु शरीर से अतिरिक्त वात को बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए कुछ असरदार उपाय भी बताए गए हैं :- मेथी दाना : रोजाना एक चम्मच मेथी के दानों (रात को भिगोए या लड्डू बनाकर) का सेवन करें। मेथी दाने वात दोष को संतुलित करने में मदद करते हैं, नसों को मजबूती देते हैं और कमर दर्द, साइटिका व जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाते हैं। मेथी के लड्डू : मेथी दानों और कच्ची हल्दी (थोड़े-से दूध में भिगोए और दरदरे पिसे), सूखे मेवे, गोंद, सोंठ, काली मिर्च, जीरा, इलायची, दालचीनी, जायफल (भुने-पिसे) और घी में भुने आटे में गुड़ की चाशनी मिलाकर लड्डू बना लें।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तीसरे दिन नेत्र शिविर, जनजागरूकता गतिविधियों एवं रैली का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अम्बेडकर नगर। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तीसरे दिन तहसील तिराहा पर एक विशेष नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने सड़क उपयोगकर्ताओं को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व, सुरक्षित यातायात व्यवहार तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधी पम्पलेट वितरित कर घर-घर तक सुरक्षित यातायात का संदेश पहुँचाने का आह्वान किया गया। इस अवसर

पर क्षेत्राधिकारी नगर नितीश तिवारी, लोक निर्माण विभाग के वैयक्तिक सहायक रामजी वर्मा, प्रभारी यातायात जय बहादुर यादव, मुख्य आरक्षी राजेश कमलेश्वर मिश्रा, आरक्षी रामप्रवेश, अतुलेन्द्र, लक्ष्मी, शिवम, सचिन, प्रवीण एवं अतुल के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी (CoERS), आईआईटी मद्रास के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसी क्रम में ग्राम पंचायत प्रतापपुर कलां में सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सुरक्षित सड़क व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया। अभियान के अगले चरण में 180 सड़क सुरक्षा मित्रों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें सड़क सुरक्षा के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया जाएगा, ताकि वे आगामी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनजागरूकता के प्रभावी दूत बन सकें। जनभागीदारी पर आधारित यह अभियान अम्बेडकर नगर में सड़क सुरक्षा को एक स्थायी जन आन्दोलन के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार पौधों का भंडारा आयोजित

कलेक्ट्रेट में आये फरियादियों, अधिवक्ताओं एवं आमजन को निःशुल्क वितरित किए गए फलदार पौधे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अम्बेडकरनगर। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जनपद के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के महा अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार पौधों का भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनता दर्शन में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आए फरियादियों, कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित अधिवक्ताओं तथा अन्य आमजन एवं कलेक्ट्रेट के कार्मिकों को निःशुल्क फलदार पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने स्वयं उपस्थित लोगों को पौधे वितरित करते हुए उन्हें अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि

वर्तमान मौसम पौधरोपण के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि इस समय पौधे रोपित कर उनका नियमित संरक्षण एवं देखभाल की जाए तो भविष्य में वे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ फल, शुद्ध वायु और हरित वातावरण का अमूल्य उपहार देंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि पौधारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित एवं स्वच्छ भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आज पौध भंडारा आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि जनसहभागिता से हरित एवं समृद्ध अम्बेडकरनगर के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

विकसित भारत कॉन्क्लेव' में श्री शिशिर बजाज को 'महाराष्ट्र के गौरव' सम्मान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ललितपुर। बजाज समूह के चेयरमैन एमेरिटस एवं बजाज फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिशिर बजाज को भारतीय उद्योग, विशेषकर चीनी एवं एथेनॉल क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, ग्रामीण विकास के प्रति समर्पण तथा सामाजिक परिवर्तन में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित 'महाराष्ट्र के गौरव' सम्मान से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित हयात रीजेंसी में मंगलवार को आयोजित आयोजित 'विकसित भारत कॉन्क्लेव' के दौरान प्रतिष्ठित कॉफी टेबल बुक 'महाराष्ट्र के गौरव' का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियों और देशभर से आए विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। कॉफी टेबल बुक के विशेष संस्करण में शिशिर बजाज के जीवन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनके

योगदान पर नौ पृष्ठों का विस्तृत आलेख प्रकाशित किया गया है। इसमें संस्थापक जमनालाल बजाज की राष्ट्रसेवा, स्वदेशी, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं मानवीय मूल्यों की विरासत को आगे बढ़ाने में शिशिर बजाज की महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तृत उल्लेख किया गया है। शिशिर बजाज के नेतृत्व में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने उल्लेखनीय प्रगति करते हुए दो चीनी मिलों से बढ़कर चौदह चीनी मिलों तथा एक डिस्टिलरी से बढ़कर छह डिस्टिलरी तक विस्तार किया। कंपनी आज देश की अग्रणी एकीकृत चीनी एवं एथेनॉल उत्पादक कंपनियों में शामिल है तथा भारत की जैव ईंधन नीति और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में समूह ने ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार किया। वर्तमान में समूह के चेयरमैन कुशाग्र नयन बजाज के नेतृत्व में बजाज समूह चीनी, एथेनॉल, उपभोक्ता उत्पाद एवं विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। बजाज एनर्जी लिमिटेड एवं ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से समूह 2430 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सतत एवं उन्नत ऊर्जा समाधान विकसित करने की दिशा में कार्यरत है।

कॉफी टेबल बुक में बजाज फाउंडेशन द्वारा जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक कार्यों का भी उल्लेख है।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षामाइक्रोप्लान के अनुसार काम करें विभाग, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ललितपुर। जुलाई माह के संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में प्रथम अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम (वि./रा.) दिनेश कुमार ने की। बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को माइक्रोप्लान के अनुसार शत-प्रतिशत गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। शुरुआत सीएमओ डा.इम्तियाज अहमद ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए की। उन्होंने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान से जुड़े सभी विभागों ने प्रथम सप्ताह में अपनी निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के आपसी समन्वय से अभियान को और अधिक

प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि जनपद में संचारी एवं वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसके बाद जिला मलेरिया अधिकारी अनिल क्रिस्टोफर मैसी ने विभागवार प्रथम सप्ताह की उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम, साफ-सफाई, मच्छरों की रोकथाम, जलभराव समाप्त करने, रोगों की पहचान और समय पर उपचार संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों से बचाव और उपचार के प्रति जागरूक किया जाएगा। अध्यक्षता करते हुए एडीएम दिनेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग के माइक्रोप्लान के अनुरूप निर्धारित गतिविधियों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जनपद की बेहतर रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें तथा पिछली कमियों को दूर करते हुए अभियान की प्रत्येक गतिविधि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला सूचना कार्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जनपद के सभी चिकित्सा अधीक्षक, सहायक मलेरिया अधिकारी, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक एवं मलेरिया निरीक्षक भी बैठक में शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग ने जनपदवासियों से अपील की है कि संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के दौरान विभागीय टीमों का सहयोग करें, अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें, जलभराव न होने दें तथा किसी भी प्रकार के बुखार या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर जांच एवं उपचार कराएं।